

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 16-06-2026

विषय सूची

जीवन की सुगमता(Ease of Living): समावेशी प्रगति की भारत की यात्रा

भारत के निर्यात में वृद्धि

ड्रोन क्रांति और आधुनिक युद्ध

एनसीईआरटी की 'डांसिंग गर्ल' विवाद

संक्षिप्त समाचार

डेंगू टीके की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

झारखंड की पारम्परिक धरोहर को भौगोलिक संकेतक (जीआई टैग)मान्यता

भारत और स्लोवाकिया ने संबंधों को व्यापक साझेदारी तक उन्नत किया

ब्रिक्स इंदौर घोषणा(Declaration)

संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने तथा होर्मुज़ जलडमरूमध्य को पुनः खोलने पर समझौता

डीआरडीओ ने बहु-स्तरीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया

भारत द्वारा 2027 के बाद राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में सर्ववैक को शामिल किए जाने की संभावना

जीवन की सुगमता: समावेशी प्रगति की भारत की यात्रा

सन्दर्भ

- भारत सरकार ने जीवन की सुगमता में सुधार के लिए किए गए प्रगति कार्यों को रेखांकित किया, जो समावेशी विकास और नागरिकों के बेहतर जीवन-स्तर में योगदान दे रहे हैं।

जीवन की सुगमता क्या है?

- जीवन की सुगमता से आशय नागरिकों की उस क्षमता से है, जिसके माध्यम से वे बुनियादी सेवाओं, अवसरों, अवसरचक्र तथा शासन तक सुविधाजनक, किफायती और सम्मानजनक तरीके से पहुँच प्राप्त कर सकें।
- इसका उद्देश्य आवास, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, परिवहन, वित्तीय सेवाओं तथा डिजिटल शासन तक पहुँच सुनिश्चित करके दैनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- यह समावेशी एवं सतत विकास का एक प्रमुख स्तंभ है।
- भारत ने आवास, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, वित्तीय सेवाओं, संपर्क-सुविधा तथा नागरिक-केंद्रित शासन तक पहुँच बढ़ाकर जीवन की सुगमता को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न पहलों की हैं।

आवास और बुनियादी सुविधाएँ

- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U): भारत ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के माध्यम से किफायती आवास तक पहुँच में उल्लेखनीय विस्तार किया है।
- पीएमएवाई-शहरी के अंतर्गत 1.25 करोड़ से अधिक शहरी आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 98 लाख से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं।
- पीएमएवाई-ग्रामीण के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा किया गया है, जिससे संवेदनशील परिवारों को सुरक्षित आश्रय प्राप्त हुआ है।

आवश्यक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), जिसे मई 2016 में प्रारम्भ किया गया था, ने स्वच्छ एलपीजी संयोजनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ग्रामीण रसोई व्यवस्था में परिवर्तन किया।

जल जीवन मिशन (JJM) ने हर घर जल के लक्ष्य के साथ नल द्वारा जल आपूर्ति के विस्तार में तीव्र प्रगति की है। जून 2026 तक 15.86 करोड़ (81.94 प्रतिशत) से अधिक परिवारों को स्वच्छ नल-जल उपलब्ध हो चुका है।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, जिसे 2014 में प्रारम्भ किया गया था, ने सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए, जिससे गाँवों में सम्मान और स्वच्छता सुनिश्चित हुई।

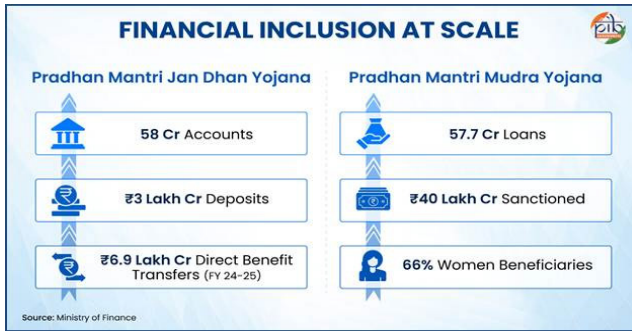
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी: शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण 2014 के 16 प्रतिशत की तुलना में 2026 में बढ़कर 82 प्रतिशत हो गया।

विश्वसनीय, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा

- सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण: सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगभग 2.86 करोड़ परिवारों को विद्युत संयोजन प्रदान किया गया।
- नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार: नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 के 76 गीगावाट से बढ़कर 2026 में 274 गीगावाट से अधिक हो गई।
- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: यह परिवारों को छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 40 लाख से अधिक परिवार पहले ही रूफटॉप सौर प्रणालियाँ स्थापित कर चुके हैं।

वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण

- जन धन-आधार-मोबाइल (जैम) त्रयी भारत की कल्याणकारी लाभ वितरण व्यवस्था की आधारशिला बन गई है।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) इसका पहला स्तंभ थी, जिसने करोड़ों वंचित नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच प्रदान की।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं के अंतर्गत ₹6.9 लाख करोड़ की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को 57 करोड़ से अधिक जमानत-मुक्त ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। मुद्रा योजना के लाभार्थियों में लगभग दो-तिहाई हिस्सेदारी महिलाओं की है।



परिवहन और संपर्क-सुविधा

- **सड़क अवसंरचना:** राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर से अधिक हो गई है।
- **अटल सुरंग, सुदर्शन सेतु तथा दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा** जैसी परियोजनाओं ने क्षेत्रीय संपर्क-सुविधा में सुधार किया है।
- **रेलवे का आधुनिकीकरण:** रेलवे विद्युतीकरण लगभग 20 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 100 प्रतिशत तक पहुँच गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों ने गति, आराम और दक्षता में सुधार किया है।
- **स्वदेशी कवच सुरक्षा प्रणाली** ने यात्रियों की सुरक्षा को सुदृढ़ किया है तथा दुर्घटनाओं में कमी लाई है।
- **क्षेत्रीय वायु संपर्क:** उड़ान योजना के अंतर्गत संचालित हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 165 हो गई है।
- **मेट्रो और तीव्र पारगमन प्रणालियाँ:** मेट्रो रेल नेटवर्क 2014 में 248 किलोमीटर से बढ़कर 1,150 किलोमीटर से अधिक हो गया है।
- **नमो भारत क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (RRTS)** ने उच्च गति वाली क्षेत्रीय संपर्क-सुविधा प्रदान की है।

शासन संबंधी सुधार

- **जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम** ने अनेक केंद्रीय कानूनों के उपबंधों में संशोधन किया है, जिससे छोटे उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर दीवानी उपचार की व्यवस्था की गई है।
- **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS):** यह मंत्रालयों, विभागों, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध एक समर्पित प्रतिपुष्टि मंच है, जो शिकायतों के निस्तारण के संबंध में नागरिक संतुष्टि की निगरानी करता है।

- **पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:** यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत अवसंरचना नियोजन को प्रोत्साहित करती है।
- इससे परियोजनाओं में होने वाली देरी कम होती है तथा सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार होता है।

चुनौतियाँ क्या हैं?

- सार्वजनिक सेवाओं तथा अवसंरचना तक पहुँच में अभी भी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएँ विद्यमान हैं। राज्यों और जिलों के बीच सेवाओं की गुणवत्ता एक समान नहीं है।
- संवेदनशील एवं वंचित वर्गों के बीच वित्तीय साक्षरता तथा डिजिटल साक्षरता का स्तर अभी भी अपर्याप्त है।
- बढ़ती ऊर्जा मांग के कारण नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण तथा विद्युत ग्रिड अवसंरचना में अधिक निवेश की आवश्यकता है।
- नव-निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव तथा उनकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर ध्यान देना आवश्यक है।

निष्कर्ष

- भारत में जीवन की सुगमता के क्षेत्र में हुआ परिवर्तन यह दर्शाता है कि लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रम, अवसंरचना में निवेश, डिजिटल शासन तथा संस्थागत सुधार किस प्रकार करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
- इन उपलब्धियों को बनाए रखते हुए उभरती चुनौतियों का समाधान करना वर्ष 2047 तक एक समावेशी, सुदृढ़ तथा समृद्ध विकसित भारत के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

स्रोत: PIB

भारत के निर्यात में वृद्धि

सन्दर्भ

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, भारत का वस्तु निर्यात मई 2026 में बढ़कर रिकॉर्ड 45.2 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गया, जो पिछले वर्ष के मई माह की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है।

परिचय

- वस्तुओं और सेवाओं दोनों के आयात में तीव्र वृद्धि के कारण भारत का कुल व्यापार घाटा बढ़कर 10.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।

भारत के शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य निम्नलिखित रहे:

- सिंगापुर – 68.96 प्रतिशत वृद्धि
- दक्षिण अफ्रीका – 116.21 प्रतिशत वृद्धि
- तंजानिया गणराज्य – 196.89 प्रतिशत वृद्धि
- इटली – 87.54 प्रतिशत वृद्धि
- श्रीलंका – 150.29 प्रतिशत वृद्धि

नोट-सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, इटली एवं श्री लंका भारत के निर्यात विस्तार के प्रमुख गंतव्य रहे हैं।

Table 1: Trade during May 2026*

		May 2026 (US\$ Billion)	May 2025 (US\$ Billion)
Merchandise	Exports	45.20	38.30
	Imports	73.41	60.86
Services*	Exports	36.76	32.46
	Imports	19.06	16.70
Total Trade (Merchandise + Services) *	Exports	81.96	70.76
	Imports	92.47	77.55
	Trade Balance	-10.51	-6.79

Fig 2: Total Trade during FY 2025-26 (April-March)*



भारत के निर्यात में वृद्धि के कारण

- पेट्रोलियम एवं वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम की ऊँची कीमतों के कारण भारत के पेट्रोलियम निर्यात, विशेषकर डीज़ल, पेट्रोल तथा विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के निर्यात मूल्य में वृद्धि हुई।
- वैश्विक स्तर पर वस्तुओं (कमोडिटीज़) की बढ़ती कीमतों ने भी निर्यात आय में समग्र वृद्धि में योगदान दिया।

- विनिर्माण क्षेत्रों का सशक्त प्रदर्शन:** निर्मित उत्पादों तथा मशीनरी की वैश्विक मांग मजबूत रहने के कारण इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात सुदृढ़ बना रहा।
- इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जिसका प्रमुख कारण उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण का विस्तार रहा।
- निर्यात बाजारों का विविधीकरण:** भारतीय निर्यातकों ने तंजानिया, श्रीलंका, बांग्लादेश तथा वियतनाम जैसे उभरते बाजारों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया।
- इस विविधीकरण से पारंपरिक निर्यात गंतव्यों पर निर्भरता कम हुई तथा क्षेत्रीय व्यवधानों के प्रति निर्यात क्षेत्र की लोचशीलता में सुधार हुआ।
- प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार:** भारतीय रुपये के मूल्यहास (Depreciation) से वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्तुओं की मूल्य-प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी।
- स्थिर आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा बेहतर लॉजिस्टिक्स व्यवस्था ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद उद्योगों को निर्यात वृद्धि की गति बनाए रखने में सहायता प्रदान की।

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्व

- बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को सुदृढ़ करना:** निर्यात में मजबूत वृद्धि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार तथा बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को समर्थन प्रदान करती है।
- निर्यात क्षेत्रों का विविधीकरण किसी एक वस्तु अथवा एकल बाजार पर निर्भरता को कम करता है।
- विनिर्माण निर्यात की वृद्धि:** इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में वृद्धि भारत के विनिर्माण पारितंत्र में सुधार का संकेत देती है। निर्यात वृद्धि रोजगार सृजन तथा औद्योगिक विस्तार को भी प्रोत्साहित करती है।
- सेवा क्षेत्र एवं व्यापार समझौतों का सामरिक महत्व:** सेवा निर्यात भारत के बाह्य व्यापार संतुलन को स्थिरता प्रदान करते हैं।
- मुक्त व्यापार समझौते (FTA) बाजारों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित कर सकते हैं, शुल्क संबंधी बाधाओं को कम कर सकते हैं तथा भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ और अधिक गहराई से जोड़ सकते हैं।

भारत के निर्यात क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ

- **वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता:** पश्चिम एशिया तथा अन्य क्षेत्रों में भू-राजनीतिक तनाव व्यापार मार्गों, नौवहन नेटवर्कों तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं।
- **आयातित कच्चे तेल पर अत्यधिक निर्भरता:** भारत की कच्चे तेल के आयात पर अधिक निर्भरता उसे वैश्विक ऊर्जा मूल्य झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। सोने तथा पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते आयात व्यापार घाटे को बढ़ाने में योगदान देते हैं।
- **अवसंरचनात्मक बाधाएँ:** उच्च लॉजिस्टिक्स तथा परिवहन लागत भारतीय निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** भारतीय निर्यातकों को चीन, वियतनाम तथा बांग्लादेश जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
- विकसित देशों द्वारा अपनाई गई संरक्षणवादी व्यापार नीतियाँ तथा गैर-शुल्कीय बाधाएँ (Non-Tariff Barriers) बाजार तक पहुँच को सीमित करती हैं।
- **विनिर्माण क्षेत्र की संरचनात्मक कमजोरियाँ:** भारत के विनिर्माण क्षेत्र को पैमाने (Scale), उत्पादकता तथा तकनीकी प्रतिस्पर्धात्मकता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- उच्च-मूल्य एवं प्रौद्योगिकी-गहन निर्यातों में सीमित विविधीकरण दीर्घकालिक निर्यात क्षमता को बाधित करता है।

हाल की सरकारी पहलें

- **निर्यात संवर्धन मिशन (EPM):** केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) की घोषणा की।
- यह निर्यात ऋण तक आसान पहुँच, सीमा-पार फैक्ट्रिंग सहायता तथा विदेशी बाजारों में गैर-शुल्कीय बाधाओं से निपटने हेतु एमएसएमई को समर्थन प्रदान करेगा।
- ईपीएम की अवधि **छह वर्षों** की होगी, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक विस्तृत रहेगी।
- इसके अंतर्गत हाल की वैश्विक शुल्क वृद्धि से प्रभावित क्षेत्रों, जैसे वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएँ तथा समुद्री उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।

- **निर्यात सहायता पैकेज:** निर्यातकों की ऋण तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 7,295 करोड़ रुपये के निर्यात सहायता पैकेज की घोषणा की।
- इसमें 5,181 करोड़ रुपये की ब्याज अनुदान (Interest Subvention) योजना तथा 2,114 करोड़ रुपये की संपार्श्विक (Collateral) सहायता शामिल है।
- **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ताएँ:** भारत नए बाजारों तक पहुँच बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है तथा वर्ष 2025 में ओमान, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम के साथ तीन मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुका है।
- वर्ष 2026 में भारत ने यूरোपियन यूनियन के साथ भी एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **डिजिटल परिवर्तन:** वाणिज्य विभाग ने व्यापार सुगमीकरण तथा व्यापारिक सूचना तंत्र को डेटा-आधारित समाधानों के माध्यम से सुदृढ़ करने के लिए अपने डिजिटल परिवर्तन एजेंडा को आगे बढ़ाया है।
- **ट्रेड ई-कनेक्ट तथा ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स (TIA) पोर्टल** जैसी पहलें साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और निर्णय-प्रक्रिया के लिए मजबूत आधार प्रदान करती हैं।

आगे की राह

- **निर्यात बाजारों का विविधीकरण:** भारत को उभरते हुए बाजारों में अपने निर्यात का विस्तार करना चाहिए तथा कुछ पारंपरिक गंतव्यों पर निर्भरता कम करनी चाहिए।
- **लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में सुधार:** निर्यात लागत और विलंब को कम करने के लिए भारत को बंदरगाहों, परिवहन नेटवर्कों तथा सीमा-शुल्क प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना चाहिए।
- **एमएसएमई एवं निर्यातकों को समर्थन:** लघु निर्यातकों के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी तथा निर्यात प्रोत्साहनों तक पहुँच को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण:** भू-राजनीतिक व्यवधानों से निपटने के लिए भारत को सुदृढ़ एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा वैकल्पिक व्यापार मार्गों का विकास करना चाहिए।

स्रोत: TH

ड्रोन क्रांति और आधुनिक युद्ध

सन्दर्भ

- यूक्रेन, लेबनान तथा पश्चिम एशिया के संघर्षों ने दिखाया है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन किस प्रकार केंद्रीय भूमिका निभाने लगे हैं।

ड्रोन युद्ध क्या है?

- ड्रोन युद्ध (Drone Warfare) से आशय ऐसे युद्ध से है जिसमें मानव रहित अथवा दूरस्थ रूप से नियंत्रित उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
- ऐसे ड्रोन वायु, भूमि, समुद्र की सतह अथवा जल के भीतर कार्य करने में सक्षम होते हैं।
- कुछ ड्रोन मानव द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जबकि अन्य अपने मिशन के दौरान स्वचालित पायलट (ऑटो-पायलट) प्रणालियों का उपयोग करते हैं।
- दूरस्थ रूप से संचालित विमान प्रणाली (RPAS): यह ड्रोन तथा उसके भू-आधारित नियंत्रण तंत्र सहित विभिन्न घटकों का समूह होता है।
- यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, चीन, भारत, रूस तथा तुर्किये ने युद्धक ड्रोन अथवा मानवरहित युद्धक हवाई वाहन (UCAV) विकसित किए हैं।
- इनका उपयोग लक्षित हमलों के लिए किया जाता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक सेनाओं की पहुँच कठिन होती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता : ड्रोन के विकास का दूसरा चरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ड्रोन हैं।
- एआई-संचालित ड्रोन स्वयं मार्ग-निर्धारण कर सकते हैं, लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं तथा “स्वार्म” (ड्रंड) के रूप में सामूहिक संचालन भी कर सकते हैं।

ड्रोन का हालिया उपयोग

- 21वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में अधिकांश ड्रोन हमले यूनाइटेड स्टेट्स की सेना द्वारा अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, यमन तथा लीबिया जैसे देशों में भूमि-आधारित लक्ष्यों पर वायु-से-भूमि मिसाइलों के माध्यम से किए गए।

- बाद में ड्रोन युद्ध को रूस, यूक्रेन, तुर्किये, अज़रबैजान तथा ईरान जैसे देशों के साथ-साथ हौथी (Houthis) जैसे गैर-राज्यीय समूहों ने भी अपनाया।
- भारत ने भी हाल के अभियानों, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर तथा पाकिस्तान के विरुद्ध जवाबी हमले शामिल हैं, में ड्रोन का उपयोग किया है।

यूसीएवी (UCAVs) का विकास

- 1960 के दशक में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की तोपखाना रेजिमेंटों ने लक्ष्य पहचान तथा मारक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से ड्रोन विकसित करने प्रारम्भ किए।
- पिछले दो दशकों में यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक, सीरिया, अफ़ग़ानिस्तान तथा यमन में आतंकवाद-रोधी अभियानों के लिए ड्रोन के व्यापक उपयोग की वैश्विक प्रवृत्ति स्थापित की। इससे सटीक हमले संभव हुए और सैनिकों के जोखिम में कमी आई।
- रूस-यूक्रेन युद्ध ड्रोन युद्ध के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ।
- रूसी और यूक्रेनी सेनाओं ने वास्तविक समय की खुफिया जानकारी तथा प्रत्यक्ष हमलों के लिए छोटे ड्रोन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया।
- वर्ष 2023 तक छोटे ड्रोन अनेक प्रकार के पेलोड ले जाने में सक्षम हो गए, जिनमें अवरक्त संवेदक (इन्फ्रारेड डिटेक्टर) से लेकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण तक शामिल हैं।

युद्ध में ड्रोन के उपयोग का महत्त्व

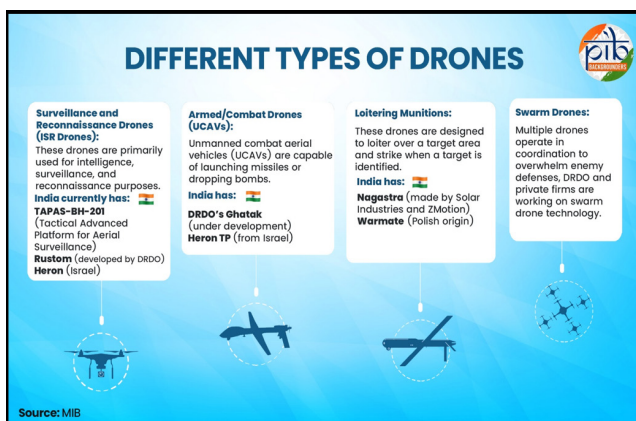
- लक्षित हमले: ड्रोन सेनाओं को अत्यधिक सटीक हमले करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे संपार्श्विक क्षति (Collateral Damage) न्यूनतम रहती है।
- सैन्य कर्मियों के लिए कम जोखिम: ड्रोन मानव रहित होते हैं, इसलिए पायलटों के जीवन को जोखिम नहीं होता तथा जमीनी सैनिकों की आवश्यकता भी कम हो जाती है।
- लागत-प्रभावशीलता: मानव-संचालित विमानों की तुलना में ड्रोन का निर्माण, संचालन और रखरखाव कम खर्चीला होता है।
- वास्तविक समय निगरानी एवं खुफिया जानकारी: ड्रोन निरंतर निगरानी, चित्रण तथा खुफिया जानकारी

उपलब्ध कराते हैं, जो आक्रामक और रक्षात्मक दोनों प्रकार के अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- **असममित युद्ध में सामरिक लाभ:** ड्रोन विशेष रूप से गैर-राज्यीय तत्वों और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, जहाँ पारंपरिक सैन्य साधनों की पहुँच सीमित होती है।

भारत की संस्थागत एवं सामरिक प्रतिक्रिया

- **एकीकृत ड्रोन पहचान एवं अवरोधन प्रणाली (IDD&IS):** इसे डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह एक व्यापक प्रति-ड्रोन (Counter-Drone) समाधान प्रदान करती है।
- यह 5-8 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन का पता लगाने, 2-5 किलोमीटर की सीमा में संचार संकेतों को बाधित (जैम) करने तथा निकट दूरी पर लेज़र-आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियारों के माध्यम से खतरों को निष्क्रिय करने में सक्षम है।
- **“भार्गवास्त्र” एंटी-स्वार्म प्रणाली:** इसे सोलर डिफेंस एण्ड एयरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह एक कम लागत वाली स्वदेशी प्रति-ड्रोन प्रणाली है, जो “हार्ड-किल” मोड में सूक्ष्म रॉकेटों का उपयोग करके ड्रोन के झुंड (स्वार्म) को नष्ट करती है।
- **भारतीय सेना की पहल:** भारतीय सेना ने अपनी रक्षात्मक तथा आक्रामक दोनों क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए निगरानी (सर्विलांस) ड्रोन तथा कामिकेज ड्रोन की बड़े पैमाने पर खरीद की प्रक्रिया प्रारम्भ की है।



आगे की राह

- आधुनिक युद्ध की आवश्यकताएँ प्लेटफ़ॉर्म-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर क्षमता-आधारित एवं

प्रौद्योगिकी-संचालित सैन्य नियोजन की मांग करती हैं। भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग, साइबर लचीलेपन, अंतरिक्ष सुरक्षा तथा संयुक्त सैन्य सुधारों (Jointness Reforms) को तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा।

- विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता (Credible Deterrence) बनाए रखने के लिए मानव संसाधन विकास, रक्षा नवाचार तथा सामरिक साझेदारियों में निरंतर निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
- तीव्र गति से बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की संप्रभुता, स्थिरता तथा सामरिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए युद्ध की बदलती प्रकृति के अनुरूप स्वयं को ढालना अनिवार्य है।

Source: TH

एनसीईआरटी की “डांसिंग गर्ल” प्रतिमा पर विवाद

सन्दर्भ

- आलोचनाओं का सामना करने के बाद एनसीआरटी ने कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्यांगना (Dancing Girl) की प्रतिमा का मूल चित्र पुनः शामिल करने का निर्णय लिया है।
- इससे पहले एनसीईआरटी ने प्रतिमा को ढके हुए धड़ (Covered Torso) के साथ प्रदर्शित करने का निर्णय लिया था।

नृत्यांगना (Dancing Girl) का परिचय

- “नृत्यांगना की प्रतिमा” लगभग 4,500 वर्ष पुरानी कांस्य प्रतिमा है, जिसे वर्ष 1926 में पुरातत्त्वविद् अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो (वर्तमान पाकिस्तान) से खोजा था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगरीय केन्द्र था।
- यह प्रतिमा लगभग 10.5 सेंटीमीटर ऊँची है तथा इसके गले में हार और भुजाओं पर बड़ी संख्या में चूड़ियाँ अंकित हैं।
- सामग्री एवं निर्माण तकनीक: यह कांस्य मूर्ति मधुच्छिष्ट ढलाई पद्धति (Lost-Wax Technique) द्वारा निर्मित की गई थी। यह धातु ढलाई तकनीक आज भी भारत

के कुछ क्षेत्रों, विशेषकर पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में प्रचलित है।

- वर्तमान में यह मूल पुरावशेष राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है।



सिंधु घाटी सभ्यता

- सिंधु घाटी सभ्यता (IVC), जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसका उत्कर्षकाल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है।
- इसका विकास मुख्यतः सिंधु नदी तंत्र के किनारे हुआ तथा इसका विस्तार वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिमी भारत के विशाल क्षेत्रों तक था।
- यह सभ्यता अपने सुनियोजित नगरों, उन्नत जल-निकासी व्यवस्था, मानकीकृत बाट एवं माप, शिल्प उत्पादन तथा दूरगामी व्यापारिक नेटवर्कों के लिए प्रसिद्ध है।
- ताँबा-आधारित मिश्रधातुओं के व्यापक उपयोग के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता (Bronze Age Civilization) माना जाता है।

सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल

हड़प्पा -पंजाब, पाकिस्तान

मोहनजोदड़ो-सिंध, पाकिस्तान

धौलावीरा -कच्छ जिला, गुजरात

कालीबंगा -राजस्थान

लोथल - गुजरात

राखीगढ़ी- हरियाणा

चन्हूदड़ो -सिंध, पाकिस्तान

गणवेरीवाला -पंजाब, पाकिस्तान

सुत्कागेंडोर -बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान

आलमगीरपुर -उत्तरप्रदेश

विवाद का महत्त्व

- इस प्रकरण ने विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों में ऐतिहासिक प्रामाणिकता और शैक्षिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन को लेकर बहस को पुनः जीवित कर दिया है।
- यह प्रश्न उठाता है कि क्या ऐतिहासिक पुरावशेषों को उनके मूल स्वरूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए अथवा उन्हें समकालीन मान्यताओं के अनुरूप आयु-उपयुक्त (Age-Appropriate) बनाने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए।
- यह विवाद इस बात को भी रेखांकित करता है कि पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों की भारत की सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत विरासत संबंधी समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- साथ ही, यह प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करते हुए पुरातात्विक साक्ष्यों की अखंडता (Integrity) को संरक्षित रखने के महत्त्व को भी उजागर करता है।

भारत एवं विदेशों में समान प्रकार की बहसें

- भारत में खजुराहो स्मारक समूह में प्रेम, मानवीय संबंधों तथा कामुकता को दर्शाने वाली जटिल मूर्तियाँ विद्यमान हैं। यद्यपि समय-समय पर उनकी स्पष्ट कलात्मक अभिव्यक्तियों को लेकर बहस होती रही है, फिर भी ये यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्मारक भारत की सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर के महत्त्वपूर्ण प्रतीक के रूप में अपने मूल स्वरूप में संरक्षित और प्रदर्शित किए जाते हैं।
- यूरोप तथा उत्तर अमेरिका में विद्यार्थियों को नियमित रूप से प्राचीन यूनानी एवं रोमन मूर्तियों के चित्रों से परिचित कराया जाता है। इनमें से अनेक मूर्तियाँ मानव शरीर को ऐसे रूप में प्रदर्शित करती हैं जिन्हें आधुनिक दर्शक स्पष्ट मान सकते हैं। फिर भी इन कलाकृतियों को सामान्यतः उनके मूल स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उनके साथ ऐतिहासिक और कलात्मक संदर्भ भी प्रदान किए जाते हैं।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

डेंगू टीके की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

सन्दर्भ

- ब्राजील ने हाल ही में अपने डेंगू टीके बुटान्टन-डीवी(Butantan-DV) के उपयोग को निलंबित कर दिया है। यह निर्णय बड़े पैमाने पर चलाए गए टीकाकरण अभियान के दौरान दो मृत्यु सहित गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्ट मिलने के बाद लिया गया।

डेंगू क्या है?

- डेंगू एक वायरस से होने वाला संक्रमण है, जो डेंगू वायरस (DENV) के कारण होता है और संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है।
- डेंगू वायरस फ्लैविविरिडी कुल का एक आरएनए वायरस है, जिसके चार प्रकार होते हैं— डीईएनवी-1, डीईएनवी-2, डीईएनवी-3 तथा डीईएनवी-4।
- किसी एक प्रकार से संक्रमण होने पर उस प्रकार के विरुद्ध आजीवन प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है, किन्तु अन्य प्रकारों के विरुद्ध केवल अस्थायी सुरक्षा मिलती है।
- लक्षण:** तेज बुखार, तीव्र सिरदर्द, आँखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, मतली, उल्टी, ग्रंथियों में सूजन तथा त्वचा पर चकत्ते।
- संचरण:** यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित मादा एडीज़ एजिप्टी मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है।
- डेंगू का संक्रमण गर्भवती माँ से शिशु में, रक्त उत्पादों के माध्यम से, अंगदान तथा रक्ताधान द्वारा भी फैल सकता है।
- रोकथाम:** डेंगू के लिए कोई विशिष्ट वायरसरोधी उपचार उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी रोकथाम मच्छरों की संख्या नियंत्रित करने तथा जन-जागरूकता बढ़ाने पर निर्भर करती है।
- डेंगू फैलाने वाले मच्छर दिन के समय सक्रिय रहते हैं। इससे बचाव का सर्वोत्तम उपाय मच्छरों के काटने से स्वयं को सुरक्षित रखना है।

चिंताएँ क्यों उत्पन्न हुई हैं?

- इस घटनाक्रम ने भारत के आगामी डेंगू टीके डेंगीऑल(DengiAll) की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ

बढ़ा दी हैं, क्योंकि दोनों टीके समान वैज्ञानिक मंचों पर आधारित हैं।

- दोनों टीके जीवित कमजोर किए गए टेट्रावैलेंट टीके (live attenuated tetravalent vaccines) हैं। इनमें डेंगू वायरस के चारों प्रकारों के कमजोर रूप सम्मिलित होते हैं।
- दोनों टीके उन टीका-उम्मीदवारों (TV003 and TV005) पर आधारित हैं, जिन्हें मूल रूप से अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा विकसित किया गया था।
- वैक्सीन-कैंडिडेट वह टीका होता है जिसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता का परीक्षण पूर्ण नियामकीय स्वीकृति प्राप्त होने से पहले किया जाता है।

बाद में इस प्रौद्योगिकी का लाइसेंस निम्न संस्थाओं को प्रदान किया गया:

- ब्राजील में बुटान्टन संस्थान (Butantan-DV हेतु)
- भारत में पैनेसिया बायोटेक (DengiAll हेतु)

एंटीबॉडी-डिपेंडेंट एन्हांसमेंट (ADE)

- ADE एक ऐसी घटना है, जिसमें पूर्व डेंगू संक्रमण या टीकाकरण के बाद बने एंटीबॉडी

बाद में होने वाले संक्रमण के दौरान वायरस को पूरी तरह निष्क्रिय नहीं कर पाते।

- शरीर की रक्षा करने के बजाय ये एंटीबॉडी वायरस को प्रतिरक्षा कोशिकाओं में अधिक आसानी से प्रवेश करने में सहायता कर सकते हैं, जिससे संक्रमण अधिक गंभीर हो सकता है।

यह कैसे होता है?

- डेंगू टीके का उद्देश्य डेंगू वायरस के सभी चार प्रकारों के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करना होता है।
- प्रसार अधिक तीव्र गति से होने लगता है।

टीकाकरण के बाद शरीर में निम्न प्रकार के एंटीबॉडी बनते हैं:

- टाइप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज (Type-specific antibodies),** जो किसी विशेष प्रकार के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं।

- **क्रॉस-रिएक्टिव एंटीबॉडीज (Cross-reactive antibodies)**, जो अनेक प्रकारों की पहचान कर सकते हैं, किन्तु अपेक्षाकृत कमजोर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।
- समय के साथ क्रॉस-रिएक्टिव एंटीबॉडीज का स्तर कम हो सकता है।
- यदि बाद में व्यक्ति किसी भिन्न डेंगू प्रकार से संक्रमित हो जाता है, तो ये कमजोर एंटीबॉडीज वायरस को रोकने में असफल हो सकते हैं। इसके विपरीत, वे वायरस को प्रतिरक्षा कोशिकाओं में प्रवेश करने में सहायता कर सकते हैं, जिससे उसका

स्रोत: TH

झारखंड की पारंपरिक विरासत को भौगोलिक संकेतक मान्यता

सन्दर्भ

- झारखंड के ग्यारह पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्रदान किया गया है।

झारखंड के जीआई-टैग प्राप्त उत्पाद

- **भगैया रेशम:** भगवानिया (भगैया) रेशम का उत्पादन गोड्डा जिले के भगैया क्षेत्र में किया जाता है। यह अपनी पारंपरिक हस्तकरघा बुनाई तकनीकों तथा उच्च गुणवत्ता वाले रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है।
- **कुचाई रेशम:** इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से सरायकेला-खरसावाँ जिले (ऐतिहासिक रूप से कुचाई के नाम से प्रसिद्ध) में आसन और अर्जुन वृक्षों पर किया जाता है।
- **केसरिया कलाकंद:** यह एक पारंपरिक मिष्ठान्न है, जो क्षेत्र की पाक-सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- **ढोकरा शिल्प:** यह भारत की सबसे प्राचीन जीवित धातु-ढलाई परंपराओं में से एक है। इसमें सजावटी तथा उपयोगी वस्तुओं के निर्माण हेतु पारंपरिक मधुच्छिष्ट ढलाई तकनीक (लॉस्ट-वैक्स कास्टिंग) का उपयोग किया जाता है।

- **तुमका चादर:** यह झारखंड के स्थानीय जनजातीय तथा शिल्पकार समुदायों द्वारा बुनी जाने वाली विशिष्ट शॉल अथवा बिछावन चादर है।
- **बरोनी चित्रकला:** यह झारखंड की पारंपरिक लोकचित्रकला है, जिसमें स्थानीय रीति-रिवाजों, प्रकृति तथा जनजातीय सांस्कृतिक परंपराओं का चित्रण किया जाता है।
- **पंचो साड़ी एवं वस्त्र:** यह झारखंड के पारंपरिक हस्तबुने वस्त्र हैं, जो अपनी विशिष्ट आकृतियों एवं स्थानीय समुदायों के बीच सांस्कृतिक महत्त्व के लिए प्रसिद्ध हैं।
- **जादोपटिया चित्रकला:** यह संथाल समुदाय द्वारा प्रचलित पारंपरिक पट-चित्रकला (स्कॉल पैंटिंग) है, जिसमें लोककथाओं, पौराणिक आख्यानों, सामाजिक परंपराओं तथा सांस्कृतिक कथाओं का चित्रण किया जाता है।



- **भोया साड़ी एवं वस्त्र:** यह झारखंड के पारंपरिक हस्तनिर्मित एवं हस्तबुने वस्त्रों में से एक है।
- **मुंडा आभूषण:** यह मुंडा जनजातीय समुदाय द्वारा निर्मित पारंपरिक आभूषण है। यह झारखंड की जनजातीय आबादी की कलात्मक परंपराओं तथा सामाजिक रीति-रिवाजों को प्रतिबिंबित करता है।
- **झारखंड बाँस शिल्प:** इस शिल्प में स्थानीय रूप से उपलब्ध बाँस का उपयोग करके उपयोगी तथा सजावटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।

भौगोलिक संकेतक (GI)

- भौगोलिक संकेतक (GI) ऐसा चिह्न है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक उद्गम होता है तथा जिनकी गुणवत्ता, विशेषताएँ अथवा प्रतिष्ठा उस स्थान से जुड़ी होती हैं।
- किसी चिह्न को भौगोलिक संकेतक के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी उत्पाद की उत्पत्ति को किसी विशिष्ट स्थान से जोड़कर प्रदर्शित करे।
- भौगोलिक संकेतकों का उपयोग सामान्यतः कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मदिरा एवं आसवित पेयों, हस्तशिल्प वस्तुओं तथा औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है।

भौगोलिक संकेतक टैग और भारत

- वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण तथा उनके बेहतर संरक्षण का प्रावधान करता है।
- इस अधिनियम का प्रशासन पेटेंट, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्नों के महानियंत्रक द्वारा किया जाता है, जो भौगोलिक संकेतकों के पंजीयक भी होते हैं।
- किसी भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि तक वैध रहता है।

स्रोत: AIR

भारत और स्लोवाकिया ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक पहुँचाया

सन्दर्भ

- भारत और स्लोवाकिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया तथा सहयोग के विस्तार हेतु 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

परिचय

- यह वर्ष 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा थी।

- दोनों देशों के बीच प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में समझौते संपन्न हुए।
- दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र क्रियान्वयन की दिशा में कार्य करने पर भी सहमति व्यक्त की।
- दोनों पक्षों ने आतंकवाद-रोधी सहयोग हेतु एक संयुक्त कार्यदल तथा एक वाणिज्य-दूतावास संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया।
- स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “दी ऑर्डर ऑफ दी व्हाइट डबल क्रॉस (प्रथम श्रेणी)” प्रदान किया, जो स्लोवाकिया का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है।

स्लोवाकिया

- स्लोवाकिया मध्य यूरोप में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। यह 1 जनवरी 1993 को चेकोस्लोवाकिया के शांतिपूर्ण विघटन के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बना।
- इसकी सीमाएँ निम्न देशों से मिलती हैं—
- उत्तर में — पोलैंड
- पूर्व में — यूक्रेन
- दक्षिण में — हंगरी
- दक्षिण-पश्चिम में — ऑस्ट्रिया
- पश्चिम में — चेक रिपब्लिक



- ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया की राजधानी, विश्व की एकमात्र राष्ट्रीय राजधानी है जिसकी सीमाएँ सीधे दो अलग-अलग देशों यथा; ऑस्ट्रिया तथा हंगरी से मिलती हैं।
- राजकीय भाषा: स्लोवाक भाषा।
- मुद्रा: यूरो (€)।

- स्लोवाकिया यूरोपियन यूनियन तथा उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दोनों का सदस्य है।

स्रोत: PIB

ब्रिक्स इंदौर घोषणा

सन्दर्भ

- इंदौर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों तथा अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें “ब्रिक्स इंदौर घोषणा” को सर्वसम्मति से अपनाया गया।
- ये निर्णय **भारत की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों एवं अधिकारियों की बैठक के समापन पर लिए गए।**

प्रमुख बिंदु

- यह घोषणा वर्तमान भू-राजनीतिक तनावों के बीच अपनाई गई है तथा **चार प्रमुख प्राथमिकताओं** यथा; किसान, खाद्य सुरक्षा, जलवायु और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है।
- ब्रिक्स देश विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनके पास **विश्व की लगभग 42 प्रतिशत कृषि भूमि** है तथा ये वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 42 प्रतिशत योगदान देते हैं।

इसके अतिरिक्त चार संस्थागत पहलों का भी प्रस्ताव किया गया है:

1. **कृषि-पारिस्थितिकी एवं पुनर्योजी कृषि उत्कृष्टता केंद्र**
 - यह प्राकृतिक, जैविक तथा पुनर्योजी कृषि पद्धतियों पर संयुक्त अनुसंधान, अनुभव-साझाकरण तथा क्षमता निर्माण के लिए एक मंच होगा।
 - मोदीपुरम स्थित भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है।
2. **डिजिटल कृषि पर ब्रिक्स नेटवर्क**
 - यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल लोक अवसंरचना तथा आँकड़ा-आधारित कृषि समाधानों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा।
 - भारत में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली इस नेटवर्क का समन्वय करेगा।

3. बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर वैश्विक मंच

- इसका उद्देश्य किसानों के बीज अधिकारों, स्वदेशी बीजों की विविधता तथा पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना है।

4. ब्रिक्स एग्रीएन (कृषि निवेश, आनुवंशिक संसाधन एवं सूचना नेटवर्क)

- यह कृषि निवेशों, बीजों तथा आनुवंशिक संसाधनों के क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करेगा।

ब्रिक्स का परिचय

- ब्रिक्स पाँच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं यथा; **ब्राजील, रूस, भारत,**

चीन तथा दक्षिण अफ्रीका का समूह है।

- बाद में **मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया तथा संयुक्त अरब अमीरात** पूर्ण सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुए।
- ब्रिक्स शब्द का प्रयोग **सर्वप्रथम वर्ष 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील** ने किया था।
- **उत्पत्ति:** एक औपचारिक समूह के रूप में ब्रिक की शुरुआत वर्ष 2006 में **सेंट पिट्सबर्ग में आयोजित जी-8 संपर्क शिखर सम्मेलन** के अवसर पर रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद हुई।
- इसी वर्ष **न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर आयोजित ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक** में इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया।
- प्रारंभ में इसे ब्रिक कहा जाता था। **वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया।**

शिखर सम्मेलन

- वर्ष 2009 से ब्रिक्स देशों की सरकारें प्रतिवर्ष औपचारिक शिखर सम्मेलनों में भाग लेती रही हैं।

न्यू डेवलपमेंट बैंक

- न्यू डेवलपमेंट बैंक (पूर्व में ब्रिक्स विकास बैंक) ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।

- यह बैंक ऋण, गारंटी, अंशपूँजी भागीदारी तथा अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक एवं निजी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है।

स्रोत : IE

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्ति तथा होर्मुज़ जलडमरूमध्य को पुनः खोलने पर समझौता

सन्दर्भ

- अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रारम्भिक समझौता हुआ है।

परिचय

- समझौते में सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल रोकने तथा 60 दिनों की वार्ता अवधि निर्धारित करने का प्रावधान है। इसमें लेबनान से संबंधित सैन्य गतिविधियाँ भी शामिल हैं।
- अमेरिका ने अपने नौसैनिक अवरोध को हटाने की घोषणा की है, जिससे होर्मुज़ जलडमरूमध्य को वैश्विक नौवहन के लिए पुनः खोले जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात तथा ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के सामान्य होने की संभावना बढ़ेगी।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य

- होर्मुज़ जलडमरूमध्य उत्तर में ईरान तथा दक्षिण में ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच स्थित है।
- यह फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जोड़ता है।
- अपने सबसे संकरे भाग में इसकी चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर है, जबकि नौवहन मार्ग दोनों दिशाओं में केवल कुछ किलोमीटर चौड़े हैं।
- भारत के लगभग आधे कच्चे तेल के आयात तथा लगभग 60 प्रतिशत प्राकृतिक गैस आयात का परिवहन इसी जलडमरूमध्य से होकर होता है।



फ़ारस की खाड़ी

- फ़ारस की खाड़ी उत्तर में ईरान तथा दक्षिण में अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है।
- यह होर्मुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से अरब सागर से जुड़ती है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री अवरोधक मार्गों (Maritime Chokepoints) में से एक माना जाता है।
- फ़ारस की खाड़ी भारत के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- वर्ष 2025 में भारत के द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आयात का लगभग 90 प्रतिशत, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात का लगभग 40 प्रतिशत तथा कच्चे तेल के आयात का लगभग 35 प्रतिशत फ़ारस की खाड़ी क्षेत्र से प्राप्त हुआ था।



स्रोत: TH

डीआरडीओ ने बहु-स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का सफल प्रदर्शन किया

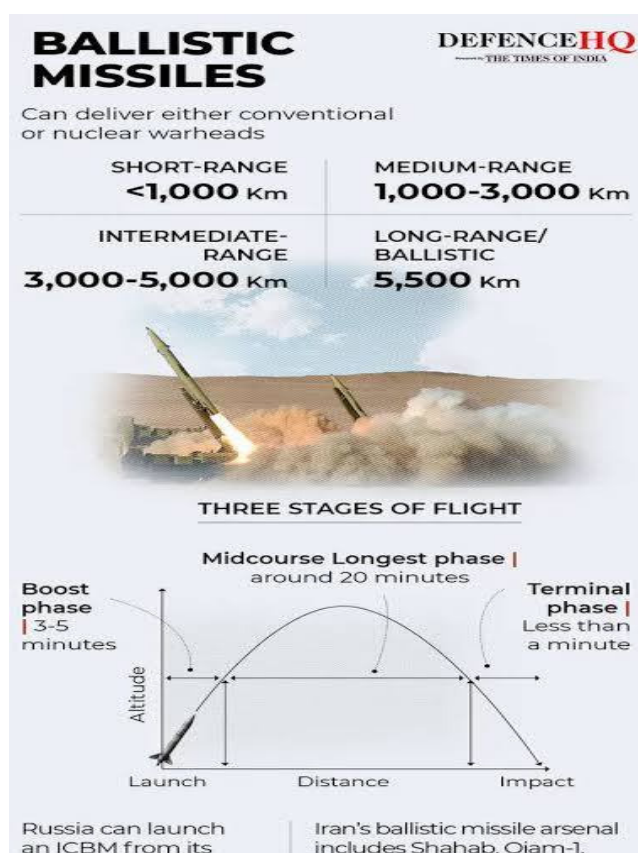
सन्दर्भ

- डीआरडीओ ने भारत की बहु-स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली (BMD) तथा मध्यम दूरी

की नौसैनिक पोत-रोधी मिसाइल (NASM-MR) के सफल सत्यापन हेतु लगातार तीन उड़ान परीक्षण संपन्न किए।

बैलिस्टिक मिसाइल क्या हैं?

- बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जिसे प्रारम्भ में रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है और उसके बाद वह मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में एक वक्राकार पथ पर यात्रा करती है, जिसे बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी (Ballistic trajectory) कहा जाता है।



मिसाइल रक्षा प्रणाली क्या है?

- मिसाइल रक्षा एक समेकित सैन्य प्रणाली है, जिसे आने वाली मिसाइलों का पता लगाने, उनको ट्रैक करने, उन्हें इंटरसेप्ट करने तथा उनके निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने से पहले नष्ट करने के लिए विकसित किया जाता है। इसका उद्देश्य नागरिक आबादी, सैन्य प्रतिष्ठानों तथा महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा करना है।
- मिसाइल रक्षा प्रणालियाँ उपग्रहों, रडारों, कमान केन्द्रों तथा अवरोधक मिसाइलों के एक ऐसे नेटवर्क पर

आधारित होती हैं, जो वास्तविक समय में मिलकर खतरों को निष्क्रिय करते हैं।

भारत की मिसाइल रक्षा संरचना

- ये डीआरडीओ के अंतर्गत बहु-स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) प्रणाली है।
- **पृथ्वी एयर डिफेंस (PAD)** इंटरसेप्टर को वायुमंडल के बाहर इंटरसेप्ट करने के लिए विकसित किया गया है। यह 50 किलोमीटर से 180 किलोमीटर की ऊँचाई पर आने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है।
- **एडवांस्ड एयर डिफेंस (AAD)** इंटरसेप्टर को अंतिम चरण में वायुमंडल के भीतर इंटरसेप्ट करने के लिए विकसित किया गया है। यह पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर 30 किलोमीटर तक की ऊँचाई पर खतरों को निष्क्रिय करने में सक्षम है।

स्तरीय वायु रक्षा कवच (Layered Air Defence Shield)

S-400 Triumph

- यह रूस द्वारा विकसित अत्याधुनिक, गतिशील भू-से-आकाश मिसाइल प्रणाली है।
- भारत ने अपनी दीर्घ-दूरी वायु रक्षा क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए इसे शामिल किया है।

मध्यम दूरी (70-100 किलोमीटर):

- **बराक-8 (MRSAM/LRSAM)**, जिसे भारत और इज़राइल ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
- यह भूमि तथा नौसैनिक परिसंपत्तियों को 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है।

लघु दूरी (25-50 किलोमीटर):

- स्वदेशी आकाश वायु रक्षा प्रणाली तथा **इज़राइल की स्पाइडर प्रणाली** रणनीतिक स्थलों एवं गतिशील सैन्य इकाइयों की सुरक्षा करती हैं।
- **मिशन सुदर्शन चक्र**: मिशन सुदर्शन चक्र वर्ष 2035 के लिए घोषित एक व्यापक दृष्टि है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम, सर्वसमावेशी राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का निर्माण करना है।
- यह पहल भारत की वायु एवं मिसाइल रक्षा क्षमताओं को एकीकृत करते हुए बहु-स्तरीय, त्वरित एवं बुद्धिमान सुरक्षा तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है।

स्रोत : IE

2027 के बाद राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में सर्वावैक को शामिल किए जाने की संभावना

चर्चा में क्यों ?

- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा विकसित तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के सहयोग से निर्मित एचपीवी टीका 'सर्वावैक' को वर्ष 2027 के बाद राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए जाने की संभावना है।

परिचय

- सर्वावैक, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मानव पैपिलोमा विषाणु (HPV) टीका है।
- वर्तमान में इसे दो-खुराक शेड्यूल के अनुसार दिया जाता है, जिसके कारण इसे राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने में सीमाएँ रही हैं।
- वर्तमान में चल रहे एक नैदानिक परीक्षण में एकल-खुराक व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसके परिणाम अगले वर्ष आने की अपेक्षा है।
- इसी वर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 14 वर्ष की बालिकाओं को लक्षित करते हुए एमएसडी के गार्डसिल टीके (MSD's Gardasil vaccine) के माध्यम से देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान प्रारम्भ किया था।

मानव पैपिलोमा विषाणु (HPV)

- एचपीवी एक सामान्य यौन-संचारित संक्रमण है। इसके अधिकांश संक्रमण लक्षणरहित होते हैं तथा स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
- प्रकृति: एचपीवी, पैपिलोमाविरीडी कुल का एक डीएनए वायरस है।
- एचपीवी से होने वाले रोग:
 - गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर (95 प्रतिशत से अधिक मामलों का संबंध एचपीवी संक्रमण से होता है)।

अन्य कैंसर:

- गुदा (anal) कैंसर
- योनि (vaginal) कैंसर
- भग (vulvar) कैंसर
- शिश्न (penile) कैंसर
- मुख एवं गले के पिछले भाग (oropharyngeal) का कैंसर।
- जननांग मस्से (Genital warts) (गैर-कैंसरकारी रोग)।

उच्च-जोखिम एवं निम्न-जोखिम प्रकार

- एचपीवी प्रकार 16 और 18 उच्च-जोखिम वाले प्रकार हैं, जो गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के अधिकांश मामलों के लिए उत्तरदायी हैं।
- भारत में 80 प्रतिशत से अधिक गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर मामलों का संबंध इन्हीं प्रकारों से है।
- एचपीवी प्रकार 6 और 11 निम्न-जोखिम वाले प्रकार हैं, जो मुख्यतः जननांग मस्सों का कारण बनते हैं।
- एचपीवी टीकाकरण:** एचपीवी टीका सबसे खतरनाक एचपीवी प्रकारों से होने वाले संक्रमण की रोकथाम करता है।
- यह टीका यौन जीवन प्रारम्भ होने से पहले, सामान्यतः 9 से 14 वर्ष की आयु में दिए जाने पर सर्वाधिक प्रभावी होता है।

क्या आप जानते हैं?

- गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है।
- भारत में प्रतिवर्ष इसके लगभग 1.25 लाख नए मामले सामने आते हैं तथा लगभग 75,000 महिलाओं की मृत्यु इस रोग के कारण होती है।

स्रोत : IE

